

2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 247/2025

दायर दिनांक: 27.10.2025

सनवान

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. कारुलाल पि. रामप्रताप जाति धाकड नि. खामणी तहसील सुनेल

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपरिस्थिति :-

प्रार्थी :- पैरोकार सरकार

अप्रार्थी :- एकतरफा

आदेश

दिनांक : 21.11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम खामणी तहसील सुनेल जिला झालावाड की आराजी खसरा नं. 445/197 रकबा 0.0128 गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी के खाते दर्ज है जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। नवीनतम नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड खसरा नं. 445/197 रकबा 0.0128 हेक्टर किरम गै.मु. चाह दर्ज है। यह कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वादग्रस्त आराजी को सिंचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कृयें खोदने एवं पम्प लगाने के लिये भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) नियमितिकरण के अनुसार चरागाह भूमि में बनाये गये चाह का राजस्व शिविर के दौरान श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो. पिडावा द्वारा आदेश दिनांक 12.11.2010 द्वारा किया गया है। यह कि उक्त नियमन आदेश में प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश होने से बाद चाह नियमन नामान्तरण संख्या 354 दिनांक 12.11.2010 से प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। नकल नामान्तरण संलग्न है। बिन्दु संख्या 3 में



उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)

वर्णित नियमों के प्रावधानों में गैर खातेदार दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। कुएं के नियमन के पश्चात मात्र लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीजधारक दर्ज किया जाना था। यह कि प्रतिवादी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात लीज को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराया गया है, न ही लीज रेन्ट की आंक कायनी की गई है। अतः उक्त नियमितकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 18.11.2025 से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. प्रार्थी परोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का गुण्दी की रिपोर्ट, ग्राम खामणी की सं. 2074-2077 की खसरा गिरदावरी, ग्राम खामणी का नामा.सं. 354 दिनांक 12.11.2010, जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता सं. 177 नकल, उपखण्ड अधिकारी पिडावा का आवंटन आदेश दिनांक 12.11.2010 की छायाप्रति पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खामणी के खाता सं. 177 के ख.नं. 445/197 रकबा 0.0126 गो.मु. चाह अप्रार्थी कारूलाल पि. रामप्रताप जाति धाकड नि. खामणी गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि गलत है। अप्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजी सिंचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खादने एवं पम्प लगाने के लिये भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) के अधीन सिवायचक भूमि में अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध कुएं को नियमितकरण कर प्रति वर्ष 24/- की लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीज पर दी गई थी परन्तु अप्रार्थी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात ना तो उक्त लीज दिनांक 12.11.2010 को रिन्यूवल नहीं



4/3
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराई है। अतः उक्त नियमितकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को लीजधारक दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थी के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थी के पास अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य नहीं है।

6. पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम खामणी के खाता सं. 177 के ख.नं. 445/197 रकबा 0.0126 गे.मु. चाह अप्रार्थी कारूलाल पि. रामप्रताप जाति धाकड नि. खामणी गैर खातेदार में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम खामणी के नामा.सं. 354 दिनांक 12.11.2010 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरण पंजिका के पैरा सं. 14 व 16 में "चाह नियमन आदेश क्र. 108-109/अभि. दिनांक 12.11.2010 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पिडावा केम्प सलोतिया के आदेश से ख.नं. 197 की 0-01 बीघा गे.मु.चाह को कारूलाल पि. रामप्रताप को 24/- वार्षिक लीज पर आवंटन की गई है। कीमत भूमि 3250/- व पट्टा शुल्क 25/- रसीद नं. 094707 से जमा राज होने पर चाह दर्ज किया गया का अंकन है। अतः जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा सरकारी भूमि ख.नं. 445/197 किरम चरागाह में से 0-01 बीघा भूमि पर बने चाह/कुए का आवंटन नियम 1979 के अधीन नियमन किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 12.11.2010 अनुसार उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा चरागाह भूमि ख.नं. 445/197 रकबा 0-01 बीघा पर अप्रार्थी कारूलाल पि. रामप्रताप जाति धाकड नि. खामणी द्वारा खोदे गये एवं कृषि भूमि की सिंचाई हेतु उपयोग में लिए जा रहे अतिक्रमित कुएं को 24/- प्रति वर्ष की लीज रेन्ट जमा कराने पर गैरखातेदार दर्ज करने के



उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में अप्रार्थी द्वारा राशि 3350/- जरिये पी 36 क्रमांक 094707 से जमा करवाई गई।

7. राजस्थान भूराजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 7 के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि आवंटन/नियमन 8 शर्तों पर किया जाता है। नियम 7 की प्रथम शर्त (i) के अनुसार इस नियम के अधीन भूमि का आवंटन/नियमन लीज पर किया जावेगा और उक्त लीज 10 वर्ष या सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुएं या पम्प सेट को उपयोग में लिए जाने का समयावधि में से - जो भी पहले हो- के लिए होगी। अतः उक्त दोनों शर्तों के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि अधिकतम 10 वर्षों के लिए लीज पर लिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के अधीन आवंटित/नियमित भूमि को खातेदारी या गैरखातेदारी के रूप में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 10 वर्षों की लीज को समाप्त होने पर प्रार्थी या लीजधारक द्वारा इसे सक्षम अधिकारी से अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। नियम 7 के प्रावधान/शर्तों निम्नानुसार हैं -

Rule 7. Conditions of allotment.- All allotment of land under these rules shall be subject to the following conditions (i) the land shall be given on Lease; (ii) One time lease money, equal to the price at the prevalent rates, recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, or the rates approved by the Inspector General of Stamps under sub-rule (1) or rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, Whichever is Higher, shall be charged. (iii) The lease shall be for a period of ten years, or for so long as the lessee uses the well or the pumping set for purpose of irrigation, whichever is less, renewable at the end of twenty years for further similar periods. The State Government may terminate the lease earlier than the period of lease when considered necessary, after giving an



उपखण्ड अधिकारी
पिपड़ा, जिला झुलवाड़ा (राज०)

opportunity of being heard to the lessee; (iv) the lessee shall have no right to sell, lease or sublet any portion of the land to any person or body of persons without the previous sanction of the Government; (v) the land shall be used only for the purpose for which it has been let out and for such allied purposes as are required for the lifting of water and its supply to the field to be irrigated; (vi) no permanent structure or buildings, except well and pump house shall be erected on the land without the previous sanction of the Government; (vii) The allottee shall have to dig the well or install a pumping set as the case may be within two years of the allotment; (viii) On failure to fulfil any of the terms and conditions of lease, the lease shall be liable to cancellation and the land shall be taken back by the Government and in the event of such resumption, the lessee shall not be entitled to any compensation for any structure etc. that he may have put up.

8. उपखण्ड अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन के बाद उक्त आवंटन नियमों के नियम सं. 8 के अनुसार आवंटन या नियमन की तारीख से 15 दिन के अंदर Form No. A में जिला कलक्टर/तहसीलदार एवं लीजधारक के मध्य लीज डीड निष्पादित कराना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष के मध्य आज दिनांक तक ऐसी कोई लीज डीड निष्पादित नहीं होना जाहिर होता है और लीज डीड के अभाव में ऐसे आवंटन/नियमन का नामान्तरण या राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में परोकार सरकार द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना लीज डीड के और लीज धारक दर्ज करने के बजाय नियम 7 के विरुद्ध टाईपिंग त्रुटीवश गैरखातेदार दर्ज करना स्वीकार किया है।

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी परोकार सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिडावा के आदेश दिनांक 12.11.2010 की सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला सारावाड़ (राज.)



का कोई उल्लेख नहीं किया है बल्कि राजस्व रिकार्ड में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल दरामद करते समय आवंटी/अतिकमी को लीज धारक दर्ज नहीं करके गलत तरीके से गैरखातेदार दर्ज करने की प्रविष्टि को दुरुस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के दौरान राजस्व कार्मिकों द्वारा लिपीकीय/टाईपिंग त्रुटी से दर्ज की गई अशुद्धि को दुरुस्त किये जाने के प्रावधान है।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम खामणी तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 445/197 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन चाह के संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

11. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम खामणी तहसील सुनेल की आराजी खसरा नं. 445/197 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन चाह में प्रविष्टि को दुरुस्त कर गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज की जावे। लीज अवधि नियमानुसार नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर तहसीलदार नियम 7 व 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला इलावाड राज
पिडावा, जिला इलावाड राज